झारखंड: बढ़-चढ़ कर चुनावी वादे

गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी राज्य में प्रमुख मुद्दे, भाजपा और कांग्रेस नीत गठबंधन कर रहे बड़े ऐलान

शिखा चतुर्वेदी

झारखंड में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। अपने-अपने मोहरे चलने के लिए राजनीतिक दल तैयार हैं। गठबंधन बनाकर एक-दूसरे को मात देने की रणनीति बनाई जा चुकी है। मौजूदा समय में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और कांग्रेस की सरकार है। पिछले चुनाव में हार का मुंह देखने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार यहां अपना प्रदर्शन सुधारने और दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। भाजपा ने चुनाव में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (एजेएसयू) के साथ हाथ मिलाया है। राज्य में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 तारीख को नतीजे आएंगे।

मतदाताओं को लुभाने के लिए झामुमो सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत 21 से 50 वर्ष आयु की पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इस योजना में फिलहाल 48,15,048 महिलाएं पंजीकृत हैं। इनमें से 45,36,597 महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना का विस्तार करते हुए सरकार ने ऐलान किया है कि दिसंबर से पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। सरकार ने यह कदम विपक्षी भाजपा द्वारा इस वादे के बाद उठाया है कि सत्ता में आने पर वह गोगो दीदी योजना लाएगी, जिसमें प्रत्येक महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपये दिए जाएंगे।

इस प्रकार की योजनाओं से राजकीय खजाने पर 9,000 करोड़ रुपये का भार पड़ने की संभावना है, लेकिन ऐसी पहल के लिए धन का इंतजाम करना बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा, क्योंकि झारखंड की निजी करों से राजस्व संग्रह की हिस्सेदारी लगभग 30.8 प्रतिशत ही है। इसके अतिरिक्त राज्य में दलित, आदिवासी और महिलाओं आदि वंचित तबकों के लिए पेंशन की आयु भी 60 वर्ष से घटा कर 50 वर्ष कर दी गई है। इससे भी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। केंद्रीय पेंशन योजना के तहत भी राज्य सरकार 240.40 करोड़ रुपये का योगदान देती है, जिसमें पात्र लोगों को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं।

पेंशन के अलावा राज्य सरकार वेतन और ब्याज भुगतान जैसी मदों में भी मोटी रकम खर्च करती है। इसलिए विकास के कार्यों पर निवेश के लिए उसके पास सीमित विकल्प बचते हैं। इस भारी दबाव के अलावा झारखंड पूंजीगत संपत्तियां पैदा करने पर अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक अपने आर्थिक संसाधनों का अधिक हिस्सा व्यय करता है। वित्त वर्ष 2025 में पूंजीगत व्यय राज्य की अर्थव्यवस्था का 7.89 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। यह वित्त वर्ष 15 में 2.91 के मुकाबले लगभग तीन गुना है। तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों का पूंजीगत सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात वित्त वर्ष 24 में लगभग 4.9 प्रतिशत था, जबकि झारखंड का 7.57 प्रतिशत था।

वित्त वर्ष 2021 में कोविड महामारी के दौर और वित्त वर्ष 15 को छोड़ दें तो राज्य का राजस्व अधिकांश वर्षों में अधिशेष ही रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में राज्य का राजस्व घाटा 2 प्रतिशत तक गिरने का अनुमान जारी किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2021 में यह सबसे अधिक 5.2 प्रतिशत के स्तर पर था। लेकिन, ऋण से जीएसडीपी अनुपात उच्च स्तर पर बना हुआ है। वित्त वर्ष 21 के बाद यह 30 प्रतिशत का स्तर पार कर 36 प्रतिशत तक दर्ज किया गया। महामारी से पहले भी इसमें लगातार वृद्धि हो रही थी। वित्त वर्ष 2019-20 में यह अनुपात 30.4 प्रतिशत था, जबकि उससे पहले के वर्ष में यह 27.4 प्रतिशत दर्ज किया गया था।

यह अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है कि जिस राज्य का राजस्व अधिशेष हो ओर वित्तीय घाटा काबू में हो, वहां ऋण का भार इतना अधिक क्यों है। ऐसा प्रतीत होता है कि खासकर महामारी के दौरान और उससे एक साल पहले ऋण संग्रह का काम हल्का रहने के कारण राज्य के सिर पर ऋणों का बोझ बढ़ा है।

राज्य की वित्तीय हालत नाजुक होने के बावजूद भाजपा ने आगामी विधान सभा चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए पांच योजनाओं का ऐलान किया है। इनमें सभी परिवारों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलिंडर दिया जाएगा। इसके अलावा साल में त्योहार के मौके पर दो सिलिंडर मुफ्त भी देने का वादा पार्टी कर रही है। इसके अलावा स्नातक और परा-स्नातक युवाओं को दो साल तक प्रति माह 2,000 रुपये देने का वादा भी भाजपा कर रही है और अगले पांच साल में 5,00,000 नौकरियां पैदा करने का दावा कर रही है। इसके साथ ही पार्टी यह भी कह रही है कि यदि वह सत्ता में आई तो खाली पड़े 2,87,000 सरकारी पदों को भरेगी।

भाजपा इस चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा जोर-शोर से उठा रही है। जहां तक राज्य की बेरोजगारी दर का सवाल है तो यह वित्त वर्ष 23-24 (जुलाई-जून) में 1.3 प्रतिशत के स्तर पर दर्ज की गई थी। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत 3.2 प्रतिशत से बहुत कम है। झारखंड भले बेरोजगारी दर कम होने के लिए अपनी पीठ थपथपाता हो, लेकिन गरीबी अभी भी यहां की मुख्य चुनौती बनी हुई है। वर्ष 2023 में जारी की गई नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबी के मामले में राज्य दूसरे नंबर पर है। राज्य के 28 प्रतिशत लोग अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। इससे अधिक 33.7 प्रतिशत लोग केवल बिहार में ही गरीबी की मार झेल रहे हैं।

झामुमो नेता कल्पना सोरेन एक चुनावी सभा में फोटो–पीटीआई

32 सीट पर निर्णायक भूमिका में महिलाएं

झारखंड की मतदाता सूची में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक होने के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सीट सहित 32 विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की भूमिका निर्णायक हो सकती है। पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की अधिक संख्या वाले 32 निर्वाचन क्षेत्रों में से 26 अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षित हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। इस निर्वाचन क्षेत्र में 2.25 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 1.15 लाख महिलाएं और 1.09 लाख पुरुष मतदाता हैं। इसी तरह, सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में 3.69 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 1.83 लाख पुरुष और 1.85 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार चंपाई सोरेन सरायकेला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सोरेन ने कथित रूप से झामुमो नेताओं के हाथों 'अपमान' और 'बेइज्जती' किए जाने का हवाला देते हुए 30 अगस्त को भाजपा का दामन थामा था। बरहेट और सरायकेला उन 32 विधानसभा सीट में शामिल हैं, जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। झारखंड में कुल 81 निर्वाचन क्षेत्रों में से 28 सीट अनुसूचित जनजाति (एसटी) एवं नौ अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित और बाकी सामान्य श्रेणी की सीट हैं। इस बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार को कहा कि झारखंड में आगामी विधान सभा चुनाव में भाजपा के लिए जीत हासिल करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सत्ता में आने की उम्मीद है। हिमंत झारखंड विधान सभा चुनाव के लिए पार्टी के सह-प्रभारी हैं।

मन की बात : डिजिटल अरेस्ट से बचाव का मोदी मंत्र

रुको, सोचो और एक्शन लो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए इससे बचने के लिए रविवार को देशवासियों से 'रुको, सोचो और एक्शन लो' का मंत्र साझा किया। उन्होंने इस बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने का भी आह्वान किया। आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 150वीं कड़ी में आज आम हो चुके डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से बचाव के लिए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर डायल करने और साइबर क्राइम डॉट जीओवी डॉट इन पर रिपोर्ट करने के अलावा परिवार और पुलिस को सूचना देने का आह्वान किया।

मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल अरेस्ट से जुड़े एक फरेबी और पीड़ित के बीच बातचीत का वीडियो भी साझा किया। इंटरनेट के तेजी से बढ़ते उपयोग के बीच ठगी का यह तरीका आम होता जा रहा है। इसमें किसी शख्स को ऑनलाइन माध्यम से डराया जाता है कि वह सरकारी एजेंसी के माध्यम से अरेस्ट हो गया है और उसे जुर्माना देना होगा। कई लोग ऐसे मामलों में डर जाते हैं और शिकार बन जाते हैं।

प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' के श्रोताओं को विस्तार से बताया कि इस प्रकार के फरेब करने वाले गिरोह कैसे काम करते हैं और कैसे खतरनाक खेल खेलते हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग और हर उम्र के लोग हैं और वे डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा देते हैं। उन्होंने कहा, 'इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। उन्होंने इससे बचने के लिए देशवासियों से 'रुको, सोचो और एक्शन लो' का मंत्र साझा किया। ये तीन चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। मैं फिर कहूंगा 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी कोई चीज नहीं है। यह सिर्फ धोखाधड़ी है, झूठ है और फरेब है। ऐसे मामलों में घबराएं नहीं। शांत रहें। जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें और सबूत सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसी धमकी नहीं देती और न ही पूछताछ करती है और न वीडियो कॉल पर ऐसे पैसे की मांग करती है।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसी राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं और आपसी तालमेल के लिए 'नेशनल साइबर कोआर्डिनेशन' केंद्र की स्थापना की गई है।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भारत को एनिमेशन की दुनिया की वैश्विक शक्ति बनाने का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। छोटा भीम, कृष्णा, हनुमान और मोटू-पतलू जैसे एनिमेशन चरित्रों की लोकप्रियता का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देश के बच्चों को भी खूब आकर्षित करते हैं और इन्हें चाहने वाले भी दुनियाभर में हैं।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एनिमेशन की दुनिया में भारत नई क्रांति की राह पर है जबकि 'गेमिंग क्षेत्र' का भी विस्तार हो रहा है और ये दुनिया में लोकप्रिय हो रहे हैं। आज देश में रचनात्मक ऊर्जा की एक लहर चल रही है और एनिमेशन की दुनिया में 'मेड इन इंडिया' और 'मेड बाइ इंडियंस' छाया हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि भारतीय प्रतिभाएं वैश्विक स्तर पर भी गेमिंग में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। एनिमेशन क्षेत्र आज एक ऐसे उद्योग का रूप ले चुका है जो दूसरे उद्योगों को ताकत दे रहा है। प्रधानमंत्री ने 28 अक्टूबर को विश्व एनिमेशन दिवस का जिक्र करते हुए लोगों से भारत को एनिमेशन की दुनिया में पावरहाउस बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। **भाषा**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
www.bankofbaroda.in

निविदा सूचना

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सुविधा प्रबंधन विभाग, GeM मुंबई, पोर्टल के माध्यम से इंटेग्रेटेड डिस्प्ले के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंडपॉइंट की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करता है।

विवरण बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in** के निविदा अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

निविदा में संशोधन सहित किसी भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र को केवल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा। निविदाकर्ता अपनी निविदा जमा करने से पहले इसका संदर्भ लें।

ऑनलाइन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 18.11.2024 को 15:00 बजे तक।

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28.10.2024

महाप्रबंधक एवं प्रमुख
(सु.प्र, सी.ओ.ए, पी.डी., सुरक्षा एवं आर.डी.पी.)

83/24-25

'सभी परियोजनाएं भाजपा शासित राज्यों में नहीं आईं'

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने निवेश को महाराष्ट्र से गुजरात ले जाने के आरोपों को रविवार को खारिज करते हुए कहा कि निवेशकों का अपना हिसाब-किताब होता है और वे ऐसी राज्य सरकार का चुनाव करेंगे जो सक्षम और कुशल हो। जयशंकर ने 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्ष में सभी परियोजनाएं भाजपा शासित राज्यों के पास नहीं आई हैं। उन्होंने कहा, 'प्रतिस्पर्धी संघवाद देश के लिए अच्छा है।'

उन्होंने कहा कि भारत-पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा दुनिया में सबसे चर्चित कनेक्टिविटी गलियारा है और इसका मुख्य 'इंटरफेस' महाराष्ट्र में होगा। विपक्ष के आरोपों

के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा कि निवेशकों का अपना आकलन होता है।

तो चुप नहीं बैठेगा भारत

विदेश मंत्री ने कहा कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी, लेकिन ऐसी घटना दोबारा हुई तो अब ऐसा नहीं होगा। जयशंकर ने कहा, 'मुंबई में जो हुआ, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए कि यहां आतंकवादी हमला हुआ और कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।' **भाषा**

ओटीटी की मार से घटी डीटीएच की कमाई

रोशनी शेखर

भारत के डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) उद्योग के राजस्व में गिरावट आने लगी है क्योंकि अब उपभोक्ता डिजिटल कंटेंट विकल्पों को प्राथमिकता देने लगे हैं। डेलॉयट इंडिया के पार्टनर (मीडिया ऐंड एंटरटेनमेंट लीडर) चंद्रशेखर मंथा ने बताया कि चार प्रमुख डीटीएच ऑपरेटर का संयुक्त राजस्व वित्त वर्ष 2022 के 12,284 करोड़ रुपये से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 11,072 करोड़ रुपये रह गया। इससे इस बात को बल मिला कि अब ग्राहक डीटीएच छोड़ डिजिटल कंटेंट यानी ओटीटी को प्राथमिकता देने लगे हैं।

हालांकि, इस बारे में बिज़नेस स्टैंडर्ड ने टाटा प्ले, एयरटेल डिजिटल टीवी और सन डायरेक्ट को ईमेल भेजा था, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। मौजूदा रुझान के आधार पर क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस ऐंड एनालिटिक्स के निदेशक (रिसर्च) पूषण शर्मा ने उम्मीद जताई है कि डीटीएच ऑपरेटर और ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म के बीच राजस्व अंतर अगले दो से तीन वर्षों में और बढ़ जाएगा। डिश टीवी के मुख्य कार्य अधिकारी कार्यकारी निदेशक मनोज डोभाल ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'पहले लोग मुख्य रूप से डीटीएच सेवाओं के जरिये टीवी देखते थे, लेकिन वैश्विक महामारी कोविड-19 से पहले हाइब्रिड मॉडल (टीवी और ओटीटी जैसी स्ट्रीमिंग सेवाएं) का रुख शुरू हो गया था, जो महामारी के बाद और तेज हो गया।' उन्होंने कहा, 'अब लोग अपने बजट के हिसाब से जहां सुविधा मिलती है वहीं कंटेंट देखने लगते हैं। टीवी खरीदने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन टीवी देखने में बिताए जाने वाले घंटों में कमी आई है, जिससे डीटीएच कंपनियों का राजस्व और ग्राहकों की संख्या प्रभावित हुई है।'

डोभाल ने कहा कि हालांकि, ग्राहक डीटीएच सेवाओं से दूर नहीं हुए हैं। लोग अभी भी डीटीएच की सेवाएं ले रहे हैं मगर दर्शकों के संख्या के दिनों की संख्या और घंटों की संख्या में गिरावट आई है। उद्योग के जानकार डीटीएच ऑपरेटर के राजस्व में गिरावट का बड़ा कारण कम ग्राहक

जानकारों का अनुमान, डीटीएच ऑपरेटर और ओटीटी प्लेटफॉर्म के बीच राजस्व अंतर अगले दो से तीन वर्षों में और बढ़ जाएगा

आधार को मानते हैं। शर्मा ने कहा कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट से संकलित आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2021 में करीब 7 करोड़ ग्राहक थे जो इस साल जून में घटकर 6.2 करोड़ रह गए हैं। विविध और उच्च गुणवत्ता वाले कंटेंट की चाह रखने वाले ग्राहकों की बढ़ती संख्या के कारण ओटीटी बाजार में अगले दो से तीन वर्षों में सालाना 10 से 12 फीसदी इजाफा होने की उम्मीद है। इसके विपरीत कमजोर ग्राहक वृद्धि और मौजूदा ग्राहकों के अन्य डिजिटल सेवाओं का रुख करने से डीटीएच राजस्व में भी 1 से 3 फीसदी की बहुत ही मामूली वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे पहले एक अन्य रिपोर्ट में क्रिसिल ने भी उल्लेख किया था कि भारतीय मीडिया कंपनियां बढ़ते डिजिटल प्रभाव को अपनाने में धीमी थीं।

ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक, डीटीएच ऑपरेटरों के कुल सक्रिय ग्राहकों की संख्या जनवरी-मार्च तिमाही के 6.19 करोड़ से बढ़कर अप्रैल-जून तिमाही में 6.21 करोड़ हो गई। बीते तीन वर्षों से अप्रैल-जून तिमाही में यह बढ़ोतरी देखी जा रही है। मंथा ने कहा, '40 लाख से अधिक ग्राहकों ने डीटीएच सेवाओं को छोड़कर डीडी फ्री डिश अथवा ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे विकल्पों को अपना लिया।' मंथा और शर्मा दोनों का कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्मों की मूल्य निर्धारण रणनीति उपभोक्ताओं को डीटीएच ऑपरेटरों से दूर जाने के लिए प्रभावित करने का बड़ा कारण साबित हो रहा है।

शर्मा समझाते हैं, 'डीटीएच सेवाओं पर आप मुख्यतः प्रसारकों द्वारा दिखाई जाने वाली सामग्री ही देख सकते हैं, जिसकी कीमत 300 से 500 रुपये के बीच होती है। इसके विपरीत, नए जमाने के फाइबर प्रदाताओं द्वारा बंडल पेशकश, जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट के साथ-साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म के विकल्प मिलते हैं उनकी कीमत 800 से 1000 रुपये के बीच होती है। कीमत में थोड़ा इजाफा कर ग्राहक बंडल विकल्पों के साथ-साथ अधिक आकर्षक विकल्प भी चुन सकते हैं।' जियो फाइबर और एयरटेल फाइबर नए जमाने के फाइबर प्रदाता हैं। वे ऐसे पैकेज की पेशकश करते हैं जिनमें हाईस्पीड इंटरनेट के साथ-साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म भी मिलते हैं। बंडल डिजिटल सेवा भी एयरटेल डीटीएच सेवा के ग्राहकों की संख्या बढ़ने का एक बड़ा कारण है। जून तिमाही में कंपनी के विवरण बताने के दौरान भारती एयरटेल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी गोपाल विट्ठल ने विश्लेषकों से कहा, 'हमारा ध्यान दक्षिण भारत के राज्यों, महाराष्ट्र और बंगाल पर है और इन्ही इलाकों में हम अभिसरण पर भी ध्यान दे रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'शुद्ध ग्राहकों की वृद्धि 1.9 लाख से अधिक थी, जो उद्योग की चुनौतियों और गिरावट के बाद भी लगातार तीसरी तिमाही में वृद्धि में रही। नतीजतन, हम बाजार हिस्सेदारी हासिल करना बरकरार रख रहे हैं। महानगरों में भी अलग-अलग पेशकशों से सकारात्मक बदलाव दिखने लगे हैं, जो ग्राहकों को एयरटेल ब्लैक की ओर आकर्षित कर रहे हैं।' कंपनी की डीटीएच सेवाएं एयरटेल ब्लैक बंडल का हिस्सा हैं, जो ग्राहकों को मोबाइल, ब्रॉडबैंड और डीटीएच जैसी कई सेवाएं एक साथ देती हैं।

डीटीएच सेवा प्रदाता भी अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ आगे आ रहे हैं। उदाहरण के लिए डिश टीवी ने ग्राहकों की बदलती मांग को भुनाने के लिए अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वाचो पेश किया है। अक्टूबर 2022 में ओटीटी के जुड़ने के बाद से वॉचो को लगभग 60 लाख सशुल्क ग्राहक प्राप्त हुए हैं।

Watch the stand-up performance by
Varun Grover

India's Biggest BFSI Event
Business Standard
BFSI INSIGHT SUMMIT
November 6, 7, 8 | Jio World Centre, Mumbai

For more details, visit **bit.ly/bsbfsi2024**

Business 50 Standard
Years of Insight

businessstandard bsindia business.standard business-standard.com